**Fourteenth Loksabha**

**Session : 6**
**Date : 22-12-2005**

**Participants : Singh Shri Prabhunath**

>

Title : Regarding need to take steps to revive Central Cooperative Banks in Bihar with hundred per cent Central share.

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार)** : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने ग्रामीण किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। इस बैंक का उद्देश्य सहकारी कृाि को बढ़ावा देना, किसानों को कृाि हेतु ऋण मुहैया कराना आदि रहा है।

बिहार प्रान्त में सैंट्रल कोआपरेटिव बैंकों की स्थिति सरकार की मदद के अभाव में अत्यंत दयनीय है। इतना ही नहीं, बिहार प्रान्त का छपरा, मधेपुरा और दरभंगा बैंकों की अनुज्ञप्ति रद्द कर गई है। इन बैंकों में किसानो का रुपया जमा है। किसान अपना जमा पैसा अपनी लड़की की शादी, कृाि कार्य आदि के लिये जब लेने जाते हैं तो बैंक द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को अपना पैसा होते हुये भी साहुकारों से मजबूर होकर ऋण लेना पड़ रहा है। इस तरह बिहार राज्य में अन्य जिलों के सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लगभग बंदी के कगार पर हैं।

इधर केन्द्र सरकार के कृाि मंत्री द्वारा वैद्यनाथन कमेटी की सैंट्रल कोआपरेटिव बैंकों के लिये की गई सिफारिश के बाद 14 हजार करोड़ रूपये की राशि मुक्त की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 35 प्रतिशत और केन्द्र सरकार द्वारा 65 प्र ातिशत निवेश किया जायेगा। बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। बिहार सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अपना 35 प्रतिशत लगा सके। वैसी स्थिति में बिहार स्थित कोआपरेटिव बैंकों को बचाने के लिये केन्द्र सरकार को फिलहाल 100 प्रतिशत लगाना होगा।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि छपरा, मधेपुरा एवं दरभंगा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक की अनुज्ञप्ति पुन: प्रदान कर बैंक चालू करायें ताकि किसानों को उनका पैसा मिल सके एवं बैंक चल सकें तथा केन्द्र सरकार द्वारा मुक्त राशि बिहार स्थित बैंकों में 100 प्रतिशत लगाते हुये बंदी के कगार पर चल रहे बैंकों को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक कदम उठायें।